The ACHIEVERS IAS ACADEMY

ACHIEVERS IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU

FOR BPSC EXAMINATION

HINDI

DATE

22/11/2023

+91 8434931877, +91 7250667974

www.achieversiaspatna.co.in

Orchid Mall, Boring Road, (Opps.- A. N. College) Patna-800001

THE HINDU National

फंसे हुए 41 लोगों की पहली तस्वीर सामने आई

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों की पहली तस्वीर मंगलवार को सामने आई, जब सोमवार को तीन इंच के पाइप के माध्यम से एक एंडोस्कोपिक कैमरा भेजा गया, जिसे सुरंग को अवरुद्ध करने वाले मलबे के माध्यम से ड्रिल किया गया था। पाइप के जरिए फल और अन्य जरूरी सामग्री भेजी गई.

900 मिमी पाइप डालने के लिए क्षैतिज ड्रिलिंग फिर से शुरू हो गई है, इसे शुक्रवार को रोक दिया गया था जब यह कठोर सामग्री से टकरा गई थी।

किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं।

4532 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था।

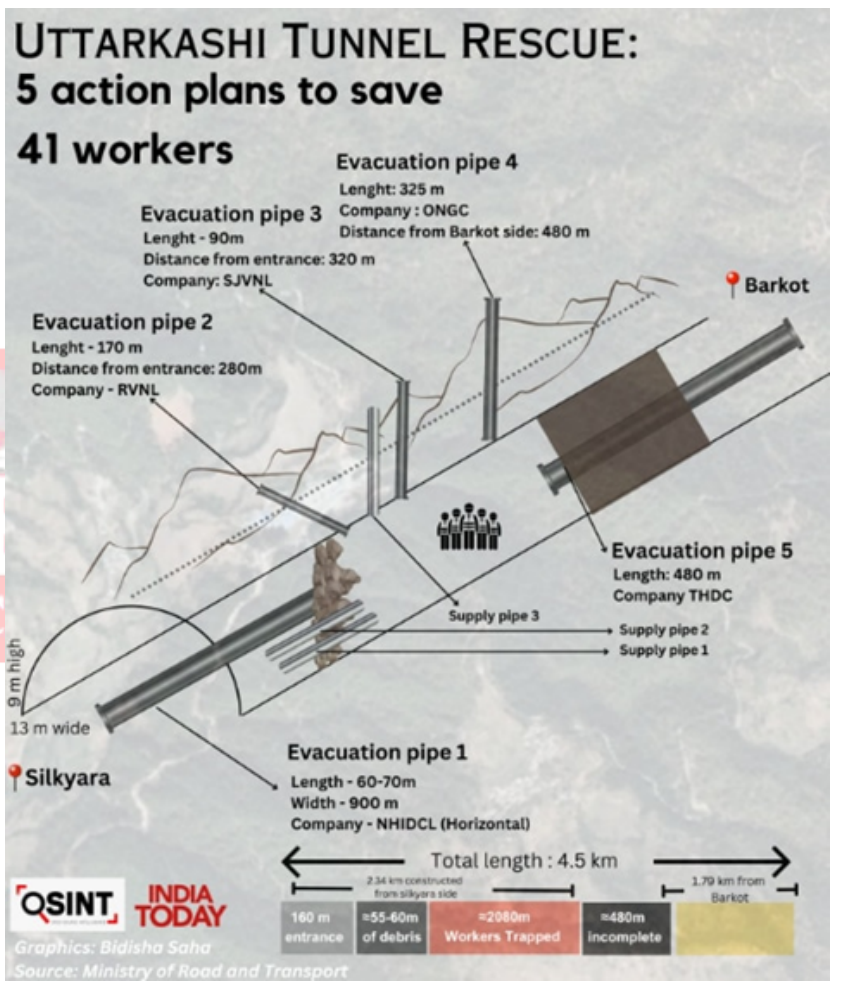

हमास प्रमुख नेतन्याहू ने गाजा युद्धविराम पर समझौते का संकेत दिया

हमास के नेता इस्माइल हनेयेह ने मंगलवार को कहा कि संघर्ष विराम समझौता करीब है और प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें बंधकों के बारे में अच्छी खबर की उम्मीद है, जो लड़ाई रोकने और बंदियों को मुक्त करने के समझौते के लिए अब तक का सबसे आशावादी संकेत है।

इस डील की मध्यस्थता कतर कर रहा है।

सूत्रों ने कहा कि इस समझौते में हमास द्वारा लगभग 50 बंधकों और इजरायली हिरासत से महिला और कम उम्र के फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई के साथ-साथ लड़ाई में कई दिनों का विराम शामिल होगा।

नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने ₹752 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ₹751.9 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि एजेएल और कांग्रेस के पदाधिकारी ने कंपनी के शेयरधारकों और दानदाताओं को धोखा दिया है।

इज़राइल ने लश्कर ए तैयबा को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है

इज़राइल ने मंगलवार को लश्कर ए तैयबा को एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया, आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह कदम आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध का समर्थन करने के इज़राइल के प्रयास के अनुरूप है।

"भारत सरकार द्वारा ऐसा करने का अनुरोध नहीं किए जाने के बावजूद, इज़राइल राज्य ने औपचारिक रूप से सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और लश्कर ए तैयबा को अवैध आतंकवादी संगठनों की इज़राइली सूची में शामिल करने के परिणाम के लिए सभी आवश्यक जांच और नियमों को पूरा कर लिया है।, "आधिकारिक इजरायली घोषणा में कहा गया है।

भारत में हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है.

इससे पहले भारत में इजराइल के राजदूत नाओर ग्लिब्बन ने बयान दिया था कि इजराइल भारत से हमास को आतंकवादी संगठन बनाने का आग्रह करता रहा है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी ने गाजा युद्धविराम के आसार जताये

ब्रिक्स द्वारा गाजा संकट पर एक असाधारण आभासी बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से पीएम मोदी बैठक में शामिल नहीं हुए और विदेश मंत्री एस जनिशकर ने इसमें भाग लिया।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसमें शामिल सभी पक्षों से तुरंत युद्धविराम घोषित करने और शत्रुता को निलंबित करने को कहा। श्री शी ने मानवीय राहत के लिए सुरक्षित मार्ग का आह्वान किया और गाजा पट्टी की नागरिक आबादी के जबरन स्थानांतरण को रोकने के लिए दबाव डाला। फ़िलिस्तीनी एन्क्लेव में पानी, ऊर्जा और बिजली की आपूर्ति भी बहाल की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस समस्या का एकमात्र समाधान दो राज्य समाधान को लागू करना है, "फ़िलिस्तीनी राष्ट्र के वैध अधिकार को बहाल करना", और एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना है। फ़िलिस्तीन .

श्री शी ने आगाह किया कि फिलिस्तीनी प्रश्न के उचित समाधान के बिना पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता नहीं हो सकती।

भारत की ओर से श्री जयशंकर ने संघर्ष में नागरिकों की हत्या की निंदा की, लेकिन युद्धविराम की चीनी मांग को दोहराना बंद कर दिया।

चीनी प्रधानमंत्री ली क्विनांग जी20 वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे

चीन ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रधान मंत्री ली क्विंग भारत के निमंत्रण पर वर्चुअल जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आशा है कि बैठक सहयोग के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करेगी और सकारात्मक योगदान देगी।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, "अस्थिर अंतरराष्ट्रीय स्थिति और आर्थिक सुधार के सामने, जी20 के लिए साझेदारी को मजबूत करना सहयोग के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और विश्व आर्थिक सुधार और वैश्विक आम विकास में सकारात्मक योगदान देना अधिक महत्वपूर्ण है।"

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को गोद लेने वाले पूल में लाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कहा कि बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले जिन बच्चों के माता-पिता एक साल से अधिक समय से उनसे मिलने नहीं आए हैं या जिनके माता-पिता या अभिभावक 'अयोग्य' हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें गोद लेने वाले पूल में लाया जाना चाहिए।

अदालत ने "अयोग्य अभिभावक" को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो "पेटेंट कराने में असमर्थ या अनिच्छुक है, नशीली दवाओं या शराब के दुरुपयोग में लिप्त है, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या उपेक्षा करने के लिए जाना जाता है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है आदि।"

अदालत ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 7 दिसंबर से संस्थानों में अनाथ, परित्यक्त, आत्मसमर्पित श्रेणी के बच्चों की पहचान करने के लिए द्विमासिक अभियान शुरू करने का आदेश दिया।.

मंत्रालय ने राज्यों से SATHEE पोर्टल के उपयोग को प्रोत्साहित करने को कहा

(SATHEE - स्व मूल्यांकन परीक्षण और प्रवेश परीक्षा के लिए सहायता, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है, यह छात्रों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा जैसी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करता है।

World

इज़राइल ने उत्तरी गाजा में हमलों का विस्तार किया, शरणार्थियों के पास आतंकवादियों से लड़ाई की

इज़रायली सैनिकों ने मंगलवार को एक शहरी शरणार्थी शिविर और एक निकट अस्पताल के बाहर फिलिस्तीनी आतंकवादियों से लड़ाई की। आतंकवादी जबलैया में एक शरणार्थी शिविर में छिपे हुए थे।

युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 1.7 मिलियन फिलिस्तीनी, गाजा की लगभग तीन चौथाई आबादी, अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। गाजा में 12700 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अन्य 4000 लापता हैं।

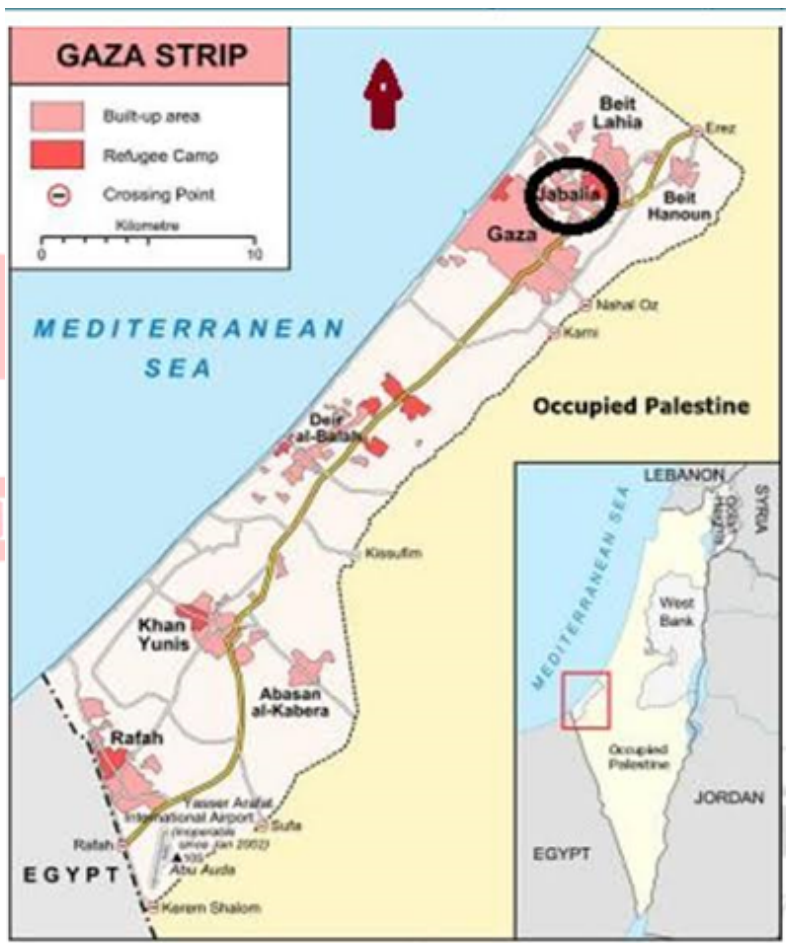

गाजा खाली कराने से पहले दो समय से पहले जन्मे बच्चों की मौत: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा कि अलशिफा अस्पताल में देखभाल कर रहे दो समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की वहां से निकाले जाने से पहले ही मौत हो गई, साथ ही यह भी कहा कि जो लोग मिस्र पहुंचे, उनमें से अधिकांश "बिना साथी के" थे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 31 बच्चों को अल शिफ़ा अस्पताल से मिस्र स्थानांतरित कर दिया था।

पाकिस्तान की अदालत ने इमरान खान की जेल में सुनवाई को अवैध माना

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को सिफर मामले में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की जेल और मुकदमे के लिए पाकिस्तानी सरकार की आधिकारिक अधिसूचना को अमान्य घोषित कर दिया, जिसमें उन पर राज्य के रहस्यों को लीक करने का आरोप लगाया गया है।

इमरान खान फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं और फिलहाल उन्हें 26 सितंबर से जहां रखा गया है, वहां उन पर मुकदमा चल रहा है।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने हालांकि बताया कि असाधारण स्थिति में किसी आरोपी के जेल मुकदमे पर कोई रोक नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र ने वार्ता से पहले कहा, विश्व वार्मिंग की सीमा को पार कर गया है

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण कार्यक्रम उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट सोमवार को जारी की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पृथ्वी पूर्व औद्योगिक काल से 2.5 डिग्री सेल्सियस से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक की गति से बढ़ रही है।

पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन 2015 के दौरान, 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को अपनाया गया था। हालाँकि रिपोर्ट कहती है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन में 43% की कटौती करनी होगी।

विश्व का तापमान इस समय औद्योगिकीकरण से पहले की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है

स्तर ।

मालदीव का कहना है कि वह बढ़ते समुद्र को मात देने के लिए द्वीप को मजबूत करेगा

समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मालदीव के जलमग्न होने का खतरा है। मालदीव के नए राष्ट्रपति ने भूमि सुधार और ऊंचे द्वीप का निर्माण करके लहरों को मात देने का वादा किया है।

एक्स ने यहूदी विरोधी भावना से भरी साइट पर दावा करने के लिए गैर-लाभकारी संस्था पर मुकदमा दायर किया

एलोन मस्क की एक्स कॉर्प जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ने गैर-लाभकारी मीडिया मामलों पर विज्ञापनदाताओं को सेमेटिक विरोधी सामग्री से भरा हुआ बताकर मंच से दूर करने के लिए मुकदमा दायर किया।

अज़रबैजान ने फ्रांस पर काकेशस में 'नए युद्ध' भड़काने का आरोप लगाया

राष्ट्रपति इहाम अलीयेव ने फ्रांस पर आर्मेनिया को हथियार देकर काकेशस में संघर्ष भड़काने का आरोप लगाया।

अजरबैजान ने हाल ही में नागोर्नो कराबाख पर पुनः कब्जा कर लिया जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित था।

काकेशस काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच का भौगोलिक क्षेत्र है।

संपादकीय

चिंताजनक उलटीगिनती

सभी देशों को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रयास करना चाहिए

संपादकीय ग्लोबल वार्मिंग पर संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के बारे में है, ब्रोकन रिकॉर्ड (बीआर) नामक रिपोर्ट सोमवार को जारी की गई थी।

इसमें कहा गया है कि भले ही राज्य विश्व के तापमान को सीमित करने के लिए बहुत प्रयास करें, फिर भी सदी के अंत तक तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा।

2030 तक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए उत्सर्जन में 28% की कटौती की जानी चाहिए। और यदि लक्ष्य तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है, तो उत्सर्जन में 42 डिग्री सेल्सियस की कटौती होनी चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश आशावादी परिस्थितियों में भी जब राष्ट्र अपने वादों का पालन करते हैं तो नेट शून्य तिथियों पर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की संभावना 14% होती है।

रिपोर्ट के कुछ निष्कर्षों में कहा गया है कि इस साल अक्टूबर तक 86 दिन ऐसे दर्ज किए गए जब तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। जबकि सितंबर अब तक का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया, जहां वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.8 डिग्री सेल्सियस ऊपर था।

पूर्व औद्योगिक स्तर का अर्थ है अवधि (1880 - 1900), औद्योगिक क्रांति से पहले की अवधि।

वर्तमान में वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

पारलौकिक कानून

राज्यों को श्रम अधिकारों को समान रूप से लागू करने की आवश्यकता है न कि संरक्षणवाद पर निर्भर रहने की

संपादकीय हरियाणा उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बारे में है जिसने हरियाणा सरकार को हरियाणा में काम करने वाली निजी कंपनियों में नौकरियों में 75% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। हरियाणा सरकार का एक अधिनियम था जिसके तहत निजी कंपनियों को 30,000 रुपये से कम वेतन वाली नौकरियों के लिए 75% कर्मचारी रखने होंगे।

अदालत ने कहा कि निजी नियोक्ताओं को खुले बाजार से लोगों की भर्ती करने से रोकना राज्य विधायिका के दायरे से बाहर है।

यह अधिनियम अनुच्छेद 14, समानता के अधिकार और अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।

इस तरह के कृत्य अन्य राज्यों को भी इसी तरह के अधिनियम लागू करने के लिए मजबूर करेंगे जिससे देश में एक कृत्रिम दीवार बन जाएगी। इससे ''इंस्पेक्टर राज'' जैसी स्थिति पैदा हो जायेगी.

अन्य राज्य आंध्र. प्रदेश और झारखंड ने भी इसी तरह के कानून पारित किए हैं और यह सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष है।

संपादकीय में कहा गया है कि यदि राज्य वास्तव में श्रम शक्ति के लिए बेहतरी चाहते हैं, तो उनके लाभ के लिए जो कानून हैं, उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। राज्य को भी नियोक्ताओं द्वारा शोषणकारी प्रथाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए।